Following is the text, in Hindi, of the Prime Minister, Dr Manmohan Singh's address at the 16th meeting of National Integration Council in New Delhi today:

"National Integration Council की 16वीं बैठक में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। वैसे तो इस Council की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है लेकिन चूंकि आज की बैठक उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगों के फौरन बाद हो रही है इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है।

यह घटनाएं ऐसी सांप्रदायिक नफरत को जाहिर करती हैं जो हमारे देश के कौमी किरदार के खिलाफ हैं और जिसकी हम सब को गहरी चिंता होनी चाहिए। एक छोटे से मामले पर एक मामूली से हादसे का नतीजा यह हुआ कि 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सौ से ज़्यादा लोग घायल हुए और कई लाख करोड़ रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

हाल के दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। इस साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार के नवादा जिले में पिछले साल के अक्टूबर महीने से छोटे मुद्दों को लेकर तीन सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरह हैदराबाद में पिछले दो सालों के दौरान रुक-रुक कर सांप्रदायिक तनाव होता रहा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं बड़ी तादाद में देखी गई हैं।

पिछले साल के दौरान पूर्वोत्तर में भी विभिन्न नस्ली गुटों एवं संप्रदायों के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ है। इस तरह के तनावों को कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। असम में पिछले साल भड़की हिंसा के शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए भी बहुत प्रयास किए गए हैं। लेकिन अभी भी दूसरी जगहों पर विभिन्न नस्ली गुटों के बीच हिंसा की वारदातें हो रही हैं। इस तरह के नए हालात में हम सबको विभिन्न सामाजिक गुटों के मिले-जुले और सहनशील सामाजिक ढ़ांचे को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की जरूरत है।

ऐसा लगता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें विभिन्न संप्रदायों के बीच छोटे- छोटे मतभेदों को बढ़ाकर उनका फायदा उठाने में कभी-कभी कामयाब हो जाती हैं। यह ताकतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। उनका सख्ती से मुक़ाबला करने का हमारी सरकार का पक्का इरादा है।

सांप्रदायिक घटनाओं का बिना वक्त खोए और निष्पक्ष और सख्त तरीके से मुक़ाबला करना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि स्थानीय प्रशासन न सिर्फ तेज़ी से छोटी घटनाओं को बड़ा रूप लेने से रोके, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाए। दंगा करने और भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली हों या किसी भी राजनैतिक दल से संबंध रखते हों। सरकार की कार्रवाई कानून के मुताबिक होती नजर आनी चाहिए ताकि सभी धर्मों के नागरिकों में यह भरोसा पैदा हो सके कि वे अन्य नागरिकों के बराबर हैं और इज्जत के साथ अपनी ज़िन्दगी जी

सकते हैं। जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, उन्हें यह सख्त हिदायत होनी चाहिए कि सांप्रदायिक तनाव के मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दंगे होने की सूरत में उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी।

यह बहस कि सांप्रदायिक हिंसा से चुनावों में किस राजनैतिक दल को फायदा होगा और किसको नुकसान, सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सांप्रदायिक दुश्मनी से किसी को भी फायदा नहीं पहुंचता। इससे तो एक civilized देश के रूप में हमारे वजूद तक को खतरा पैदा हो सकता है। मैं सभी राजनैतिक दलों और Media से आज यह अपील करना चाहूंगा कि वह न तो सांप्रदायिक वाक्यात को राजनैतिक रंग दें और न ही उनसे राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक में सांप्रदायिक सदभाव बढ़ाने के अच्छे सुझाव सामने आएंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर तबकों के हमारे भाई-बहनों के विरूद्ध हो रहे अत्याचार भी कोई कम चिंता की बात नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी के 60 साल के बाद भी इन तबकों के खिलाफ हो रहे अपराध हमें परेशान कर रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही इस तरह की घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 3 सालों के दौरान हर साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अत्याचार के लिए 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह की हिंसा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि इन तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की लगातार कोशिश की जाए।

हमारा आर्थिक विकास तभी पूरा और संतोषजनक कहा जा सकता है जब इससे आम आदमी और कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचे। कमज़ोर और गरीब वर्गों को बराबर के मौके न मिल पाना देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम किसी भी तबके को यह महसूस नहीं होने दे सकते कि वह मुख्य समाज से अलग थलग है। हमने कमजोर तबकों के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उनको देश के विकास का ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। अभी हाल ही में संसद में Manual Scavenging Rehabilitation Bill पास हुआ है, जिससे इस अमानवीय प्रथा को ख़त्म करने में मदद मिलेगी।

लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी हमारे लिए बड़ी चुनौती हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने समाज में असमानता कम करने और अभाव दूर करने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस दिशा में आप सब के सुझावों का स्वागत करूंगा।

हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार और अन्य तरह की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। कोई भी देश सही मायनों में तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाएं बेझिझक सार्वजनिक स्थानों पर जा सकें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते को चुन सकें। हमने महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। अब कानून लागू करने वाली एजेंसियां ऐसे मामलों में ज्यादा

प्रभावी कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से दूर नहीं की जा सकती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारी सोच में बदलाव आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक में हमारी महिलाओं के प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाने के लिए अच्छे सुझाव सामने आएंगे।

आज हम ऐसी जुड़ी हुई दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत से मामलों में राष्ट्रीय सीमाओं का बहुत महत्व नहीं रह गया है। मैं यहाँ सोशल मीडिया का ज़िक्र करना चाहूँगा। हाल की सांप्रदायिक हिंसा के कुछ मामलों के पीछे कुछ ऐसे नकली Videos का circulation सामने आया है जिनसे लोगों में दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत पैदा हुई। इससे पहले साल 2012 में सोशल मीडिया का दुरूपयोग करके हमारे उत्तर-पूर्व के उन भाई-बहनों के मन में दहशत पैदा की गई जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे। इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने रोजगार छोड़कर कुछ समय के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वापस जाना पड़ा।

Social Media के ज़रिए नौजवानों को नई जानकारी मिलती है और उन्हें नई सोच का पता चलता है। इसका इस्तेमाल समाज में आपसी रवादारी और भाईचारा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। Social Media अपनी राय और नज़रिया आज़ादी से जाहिर करने का जो मौका देता है उसे कायम रखने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम शरारती और समस्या पैदा करने वाले लोगों को सोशल मीडिया का दुरूपयोग न करने दें। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के दुरूपयोग के मामले पर आज इस बैठक में ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में Industry, गैर सरकारी संगठन और Civil Society सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। National Integration Council एक ऐसा Forum है जो समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आम राय बनाने में मदद कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक में कई ऐसे अहम् मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद मिलेगी जिनका संबंध हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने से है।"

***